

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 47/23

GCMS NO 2023/117

कानजी पुत्र श्योराम जाति गुर्जर निवासी छाहरा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
अपीलांत

बनाम

1. बन्नू उर्फ बानू पुत्र श्योराम जाति गुर्जर निवासी छाहरा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई

माधोपुर
2. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरुद्ध मु0नं0 91/15 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.22 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा

अभिभाषक रेस्पो0 श्री राधेश्याम बैष्णव


दिनांक 02.04.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.22 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने एक दावा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहखातेदारी की भूमि खसरा न0 261 रकबा 0.01 है0, 262 रकबा 0.37 है0, 303 रकबा 0.66 है0, 304 रकबा 0.02 है0 1997 रकबा 0.43 है0 ग्राम चूली एवं खसरा न0 602 रकबा 0.19 है0, 603 रकबा 1.15 है0 ग्राम सलेमपुर में स्थित है। इस भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की मां नारायणी बेवा श्योराम का इन्तकाल हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 नारायणी बेवा श्योराम के एक मात्र वारिस है। पक्षकारों ने भूमि को अपने अपने हिस्से अनुसार अलग अलग बांट रखा है। इसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। भूमि सहखातेदारी की होने से आये दिन विवाद बना रहता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को राजस्व अभियान के दौरान भूमि विभाजन कराने को कहा परन्तु प्रतिवादी ने आनाकानी की एवं भूमि विभाजन में कोई रुचि नहीं दिखाई। इस कारण दावा विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर भूमि खसरा न0 261 रकबा 0.01 है0, 262 रकबा 0.37 है0, 303 रकबा 0.66 है0, 304 रकबा 0.02 है0 1997 रकबा 0.43 है0 ग्राम चूली एवं खसरा न0 602 रकबा 0.19 है0, 603 रकबा 1.15 है0 ग्राम सलेमपुर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मीटस एण्ड बाउन्डस से विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के हिस्से के कब्जे काश्त में ना तो स्वयं बाधा पैदा करे ना ही अन्य किसी से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का





राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांत/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की अपील पर सुनी गई।

अपीलांत के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से परे होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जल्दवाजी में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की कोई विधिक तुलना नहीं कर कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित की है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 14.11.22 को पारित की है इसमें बंटवारा स्कीम तैयार की गई है इससे पूर्व अपीलांत को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया उनकी मौजूदगी में तैयार नहीं की गई तथा तहसील कार्यालय में पटवारी हल्का द्वारा साज कर तैयार की गई है। जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मंडल द्वारा कई नजीरो में स्पष्ट मत पारित किया है कि बंटवारा स्कीम पक्षकारों की मौजूदगी में तहसीलदार द्वारा तैयार की जानी चाहिए। उक्त प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा गलत रूप से रेस्पों से साज कर बंटवारा स्कीम तैयार की है तथा इस पर यह अंतिम डिक्री अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की है। जबकि वास्तविकता यह है कि मौके पर कोई बंटवारा स्कीम तैयार नहीं की है रेस्पों उक्त निर्णय की आड़ में अपीलांत को उसके कब्जे काश्त की भूमि को हड़पना चाहता है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। वास्तविकता यह है कि श्योराम के तीन पुत्र थे। बन्नु कानजी एवं बाबूलाल तथा अपीलांत के पिता का देहान्त सन 1993 में हो चुका था। बाबूलाल अविवाहित व विकलांग था जिसने उत्तराधिकारी बतौर सुरेश पुत्र कानजी को सामाजिक रीति रिवाज अनुसार गोद ले लिया था। आकस्मिक रूप से बाबूलाल की मृत्यु हो जाने तथा श्योराम ने अपने तीनों पुत्रों को अपनी खातेदारी कृषि भूमि को विभाजित कर दी थी इस प्रकार रेस्पों न0 1 ने बाबूलाल के पुत्र को पक्षकार नहीं बनाया गया। जबकि जमाबंदी सम्वत 2046 से 2049 में अंकित नामा0 संख्या 235 दिनांक 10.5.93 व नामा0 संख्या 195 दिनांक 1.6.92 के द्वारा मृतक श्योराम की विरासत अपीलांत रेस्पों व बाबू के नाम दर्ज हुई है। लेकिन किस आधार पर बाबू का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कर दिया। यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया। इसके अलावा श्योराम के एक पुत्री गुलाब भी मौजूद थी। जमाबंदी सम्वत 2074 में ग्राम सलेमपुर की भूमि में सहखातेदारी में गुलाब के नाम का अंकन जिसे नामा0 संख्या 963 दिनांक 3.5.18 के हकत्याग द्वारा दर्शाया गया है इससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा वर्ष 2015 में वाद पत्र पेश किया है तथा वादी ने गुलाब का नाम वाद पत्र में नहीं दर्शाया है इससे स्पष्ट है कि वादी रेस्पों संख्या 1 ने साज कर उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। जो प्रारंभ से ही शून्य आदेश की श्रेणी में आती है। इस प्रकार वाद पत्र के लिए समस्त आधार आपस में विराधाभासी है इस समस्त बातों पर गौर किये बिना उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की कोई सूचना अपीलार्थी को नहीं थी। दिनांक 22.7.23 को बाबू के पोते जीतू पुत्र सुरेश ने खाते की नकल हेतु जमाबंदी देखी


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

तब मालूम हुआ कि खेतों का विभाजन होकर जमाबंदी में दर्ज हो गया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त की जाकर जानकारी से अपीलान्त की अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपीलान्त की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.22 को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो० के अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात संयुक्त

खातेदारी की आराजीयात होने से पक्षकारों के मध्य आये दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय में बंटवारे का वाद पेश किया गया था। पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से अपने अपने हिस्से पर फसल काश्त कर रहे हैं। भूमि सहखातेदारी की होने एवं विधिवत बंटवारा नहीं होने

के कारण ही विभाजन कराना न्याय हित में आवश्यक है। भूमि का विभाजन विधिवत कराने हेतु वादी/रेस्पो० संख्या 1 द्वारा वाद पत्र पेश किया गया था। अपीलान्त के अधिवक्ता द्वारा अदालत

मातहत में दिनांक 17.10.16 को उपस्थित होकर वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किये जाते पर प्राथमिक डिक्री अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई। यदि अपीलान्त प्राथमिक डिक्री से

व्यथित था तो उनको तत्समय ही अपील पेश करनी चाहिए थी। जो उनके द्वारा नहीं की गई है। अपीलान्त द्वारा दौराने प्राथमिक डिक्री यह कथन नहीं किया कि मृतक श्योराम के तीन पुत्र थे।

बाबूलाल को वादी/रेस्पो० संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। जबकि इस बात का उज्र अपीलान्त को प्राथमिक डिक्री के समय ही करना चाहिए था। इस प्रकार अपीलान्त का यह कथन साबित नहीं होता है। इसी प्रकार अपीलान्त का कथन रहा कि अपीलान्त को मौखिक एवं

दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलान्त द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जानबुझकर कोई मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

अपीलान्त का कथन रहा कि बंटवारा स्कीम पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई है जो राजस्व मंडल के नियम 21 के विरुद्ध है। जबकि पत्रावली में उपलब्ध बंटवारा स्कीम दिनांक 25.12.20 पटवारी हल्का

एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर तैयार की गई है। बंटवारा स्कीम मौके पर वादी एवं प्रतिवादी को पढकर सुनाई गई है जिस पर गांव के स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर कराये गये हैं। इस प्रकार अपीलान्त का यह कथन मनगढन्त है। पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधि के

प्रावधानों के तहत मीटिंग्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर एवं राजस्व मंडल अजमेर के नियम 21 की पालना करते हुए बंटवारा स्कीम तैयार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के तहत ही अपीलान्त निर्णय व डिक्री पारित की

गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलान्त की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। अपीलान्त आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जो कि जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 से स्पष्ट है। जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। विधिवत बंटवारे के बिना किसी भी खातेदार का हिस्सा तय नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो० संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दावे में प्राथमिक डिक्री दिनांक

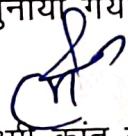
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

17.10.16 को वादी एवं प्रतिवादी द्वारा सहमति दिये जाने पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अपीलांट का कथन रहा कि विभाजन स्कीम केवल मात्र पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है। पत्रावली में उपलब्ध विभाजन स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर तैयार की गई है जिस पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर होना इस बात को प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन सिद्ध नहीं होता है। अपीलांट का कथन रहा कि मृतक श्योराम के तीन पुत्र थे परन्तु अपीलांट द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है जिससे की यह सिद्ध हो सके कि मृतक श्योराम के दो पुत्र नहीं होकर तीसरा पुत्र बाबूलाल भी था। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 में विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिसे विधिवत बंटवारा कराने का अधिकार वादी को प्राप्त होने से ही वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सहमति से दिनांक 17.10.16 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार से विवादित आराजीयात की रिकार्ड एवं मौके की स्थिति के अनुसार कुरेजात प्राप्त की जाकर, प्राप्त कुरेजात अनुसार विधिवत रूप से वादी का वाद पत्र डिक्री किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी के प्रकरण संख्या 91/15 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




(लक्ष्मी कान्त बालोद)
राजस्थान अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर